भारत-रूस मित्रता के मजबूत वैश्विक संदेश

डॉ.ब्रह्मदीप अलून
(विदेश नीति के जानकार)

कूटनीति की सफलता अक्सर मनोवैज्ञानिक विजय पर आधारित होती है और पुतिन की भारत यात्रा ने यही सिद्ध किया. भारत द्वारा दिए गए सम्मान,रेड कार्पेट स्वागत और उच्च स्तरीय वार्ताओं ने दुनिया को संदेश दिया है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अडिग है. इस यात्रा ने यह भी दिखाया कि रूस वैश्विक दबावों के बीच भी अलग-थलग नहीं है और भारत उसके लिए भरोसेमंद साझेदार बना हुआ है. इसके साथ ही अमेरिका और यूरोप के दबावों से अप्रभावित रहकर भारत ने तीसरी दुनिया के आत्मविश्वास को भी बढ़ाया है. जाहिर है ग्लोबल साउथ के देशों ने भारत को एक आत्मविश्वासी,संतुलित और प्रभावशाली शक्ति के रूप में देखा. यह बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है.

रूस दशकों से भारत का प्रमुख रक्षा भागीदार और आपूर्तिकर्ता रहा है. वर्तमान में रक्षा सहयोग भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. यह दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम समझौते द्वारा निर्देशित है. वर्तमान में चल रही द्विपक्षीय परियोजनाओं में टी-90 टैंकों और एसयू-30-एमकेआई विमानों का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन,मिग-29-के विमान और कामोव-31 की आपूर्ति,मिग-29 विमानों का उन्नयन आदि शामिल हैं. भारत की मिसाइल प्रणाली,युद्धक विमानों से लेकर परमाणु पनडुब्बियों तक,अधिकांश रणनीतिक हथियारों का आधार रूसी तकनीक पर आधारित है. अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा सहयोग उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है. रूस भारत को रियायती दरों पर तेल और गैस उपलब्ध कराता है,जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा स्थिर रहती है. इसी तरह अंतरिक्ष,विज्ञान,उर्वरक,फार्मा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी निरंतर संवाद और सहयोग बना हुआ है. इस प्रकार दोनों देश अपनी आवश्यकताओं के आधार पर दीर्घकालिक रणनीतिक तालमेल विकसित कर रहे हैं.

भारत में पुतिन की हालिया यात्रा ऐसे समय हुई,जब वैश्विक राजनीति अत्यंत जटिल और दबावपूर्ण स्थिति में थी. एक ओर रूस पश्चिमी प्रतिबंधों तथा यूक्रेन युद्ध की चुनौतियों से गुजर रहा है,वहीं भारत पर अमेरिका और यूरोपीय देशों का लगातार दबाव था कि वह रूस से अपनी निकटता कम करे. इस कारण माना गया कि मोदी और पुतिन दोनों ही दबाव में होंगे . लेकिन दोनों नेताओं ने ऐसे किसी दबाव को दरकिनार कर अपनी स्वतंत्र रणनीति को प्राथमिकता दी. इस दौरान दुनिया ने भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को महसूस किया जो राष्ट्रीय हितों के लिए किसी भी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं हुई.

इस समय भारत के लिए ट्रम्प और पश्चिमी गठजोड़ के चुनौतियां बढाई है की भारत को रूस से दूरी बनानी चाहिए. तेल आयात,रक्षा खरीद और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर अमेरिका के संकेत स्पष्ट यहीं है. इसके बावजूद भारत ने पुतिन की यात्रा को न केवल अभूतपूर्व बनाया बल्कि 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया. इस दौरान रक्षा,ऊर्जा,रोजगार,उर्वरक, स्वास्थ्य,खाद्य सुरक्षा, शिपिंग, शिक्षा और तकनीकी

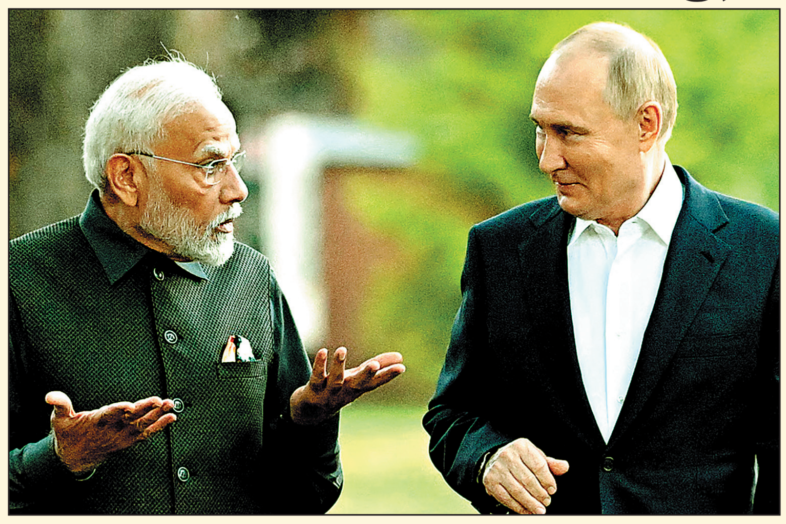

विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में कई समझौते हुए. रूसियों के लिए भारत में 30-दिन की निःशुल्क ई-टूरिस्ट वीजा का ऐलान हुआ,इससे सांस्कृतिक, पर्यटन और लोगों के बीच आदान-प्रदान को बल मिलेगा. भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग जारी रहेगा . इसके साथ ही रूस ने भारत को निरंतर तेल व गैस आपूर्ति की गारंटी दी. इन समझौतों से पता चलता है कि भारत दबाव में नहीं है और दुनिया को भी यह स्पष्ट संदेश गया है कि भारत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हितों और संतुलन की राजनीति के बीच अपना स्वतंत्र रास्ता स्वयं तय करेगा.

इस समय रूस यूक्रेन युद्द को रोकने के लिए पुतिन पर गहरा दबाव है . रूस से सहयोग करने वाले देशों पर भी वैश्विक स्तर पर दबाव डाला जा रहा है. खासकर पश्चिमी देश रूस को ग्लोबल दक्षिण से दूर करने की कोशिश करता रहे है. पुतिन की यात्रा भारत के लिए भी किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं थी . लेकिन भारत की इस यात्रा ने यह स्पष्ट किया कि रूस अभी भी विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण साझेदार है. पुतिन ने इस यात्रा के माध्यम से यह प्रदर्शित किया कि रूस के लिए भारत केवल रक्षा सहयोगी नहीं,बल्कि एक व्यापक आर्थिक और रणनीतिक भागीदार है.

रूस इस समय कई स्तरों पर बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है. सबसे बड़ी चुनौती यूक्रेन युद्ध के चलते जारी पश्चिमी प्रतिबंधों की है,जिसने उसकी अर्थव्यवस्था,बैंकिंग प्रणाली,निर्यात और वैश्विक व्यापार पर गंभीर असर डाला है. ऊर्जा निर्यात पर निर्भर रूस को यूरोपीय बाज़ार लगभग खोना पड़ा,जिससे उसकी राजस्व संरचना पर दबाव बढ़ा है. तकनीकी प्रतिबंधों के कारण आधुनिक उपकरण,माइक्रोचिप्स और हाई-टेक मशीनरी की उपलब्धता सीमित हो गई है, जो सैन्य और औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित कर रही है. कूटनीतिक स्तर पर भी रूस को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं. अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के कारण कई पारंपरिक सहयोगियों ने दूरी बना ली है. इसके अलावा,युद्ध की लंबी अवधि ने रूस की आंतरिक राजनीति, संसाधनों और जनमानस पर भी असर डाला है.

वहीं भारत वर्तमान समय में जटिल और बहुस्तरीय भू-रणनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है. सबसे बड़ी चुनौती चीन का विस्तारवादी रुख है,लद्दाख में सैन्य दबाव,अरुणाचल पर अवैधानिक दावे हों या हिंद-प्रशांत में आक्रामक नौसैनिक मौजूदगी. चीन और पाकिस्तान की सामरिक मोर्चाबंदी भी भारत के लिए चुनौती । रही है. इन सबके बीच भारत को बहु-ध्रुवीय विश्व में संतुलन साधने,रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने और पड़ोसी क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करने की निरंतर चुनौती का सामना करना बड़ रहा है. हिंद महासागर में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी भारत से सक्रिय समुद्री कूटनीति की मांग करती है.

पुतिन की भारत यात्रा दोनों देशों के लिए रणनीतिक,आर्थिक और भू-राजनीतिक रूप से प्रभावकारी रही है. भारत को ऊर्जा, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में स्थिरता और विविधीकरण का महत्वपूर्ण फायदा मिलने की उम्मीदें बड़ी है. रूस भारत का सबसे विश्वसनीय रक्षा साझेदार रहा है और इस यात्रा से साझा रक्षा परियोजनाओं,स्पेयर-पार्ट आपूर्ति,परमाणु ऊर्जा सहयोग तथा नए तकनीकी क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूती मिलेंगी. ऊर्जा क्षेत्र में रूस का किफायती तेल भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा स्तंभ बना हुआ है और इसके निर्बाध बने रहने से भारत और रूस दोनों देशों को आर्थिक लाभ होगा. वहीं रूस की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है. यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच भारत ऐसा बड़ा राष्ट्र है जो रूस से निरंतर आर्थिक संबंध बनाए रखे हुए है.

> भारत रूस को न केवल विशाल बाजार देता है,बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रणनीतिक संवाद का अवसर भी प्रदान करता है,जिससे रूस की वैशिक प्रासंगिकता बरकरार रहती है. भारत और रूस वैश्विक शक्ति-संतुलन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. भारत अपनी उभरती अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता, जनसांख्यिकीय शक्ति और लोकतांत्रिक मॉडल के कारण विश्व व्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाता है. वहीं रूस ऊर्जा, रक्षा,अंतरिक्ष तकनीक और भू-राजनीतिक प्रभाव के कारण अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का अनिवार्य हिस्सा है. दोनों देशों की ऐतिहासिक मित्रता और रणनीतिक सहयोग एशिया से लेकर वैश्विक मंचों तक स्थिरता सुनिश्चित करता है. इसलिए भारत और रूस के बिना एक संतुलित,सुरक्षित और बहुध्रुवीय दुनिया की कल्पना अधूरी है. बहरहाल पुतिन की यात्रा ने यह दिखाया की भारत-रूस के बीच एक भरोसेमंद सामरिक साझेदारी हैं जो समय,दबाव और वैश्विक परिस्थितियों से परे हैं. यह संदेश अमेरिका,चीन और पश्चिमी दुनिया तक गया है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर कायम है और रूस एशियाई शक्ति-संतुलन में अब भी प्रभावशाली खिलाड़ी है.

व्यंग्य

भौंकने की जरूरत क्यों?

श्याम यादव

वह तो एक माननीय का पालतू था, जो उतने ही शालीन अंदाज़ में चला, जितने शालीन होने की अपेक्षा कभी-कभी माननीयों से भी कर ली जाती है. उसने न भौंकने की जरूरत महसूस की, न दौड़ने की. युधिष्ठिर के साथ कहते हैं, एक कुत्ता स्वर्ग गया था और देवताओं ने भी उतना हल्ला नहीं मचाया होगा, जितना अब एक कुत्ते के संसद में प्रवेश करने पर मच गया है. सारे अख़बार और टीवी चैनल उसी कुत्ते की सांसों की गणना कर रहे हैं, मानो वह सिर्फ इमारत में नहीं घुसा, लोकतंत्र की रीढ़ में भी हलचल पैदा कर गया हो. यह कोई पहली बार नहीं था जब कुत्ता राष्ट्रीय सुर्खियों में आया हो. कभी सर्वोच्च अदालत ने सड़कों पर घूमते कुत्तों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे और इस बार सत्ता के गलियारों में आते ही वही प्राणी वैधानिक बहस का नया बिंदु बन गया.

संसद में आया यह कुत्ता न आवारा था, न उद्दंड. वह तो एक माननीय का पालतू था, जो उतने ही शालीन अंदाज़ में चला, जितने शालीन होने की अपेक्षा कभी-कभी माननीयों से भी कर ली जाती है. उसने न भौंकने की जरूरत महसूस की, न दौड़ने की. न उसने टांग उठाकर क्षेत्रीय प्रभुत्व जताया. वह जितनी चुप्पी से आया, उतनी ही चुप्पी से चला गया, लेकिन देश में शोर ऐसा उठा मानो किसी संवैधानिक संस्था पर हमला हो गया हो. कुत्ते के प्रवेश को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज़ रही. कुछ लोगों को लगा कि यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान है, जबकि कुछ ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने वालों को समझाया कि लोकतंत्र को खतरा कुत्तों से नहीं, उन इंसानों से है जो बिना आवाज़ किए भी काट लेने की क्षमता रखते हैं. बड़े-बड़े टीवी चैनलों ने भी रात भर पैनल बैठाकर कार्यक्रम किए. चुनाव, अर्थव्यवस्था, रोजगार जैसे विषयों पर सीमित दिलचस्पी रखने वाले वही चैनल इस 'कुत्ता-कांड' पर विशेषज्ञ बुलाकर बता रहे थे कि यह घटना किस दल को राजनीतिक लाभ पहुंचा सकती है और कौन-सा गुट इससे शर्मिंदा होना चाहिए.

सोशल मीडिया ने भी अपने हिसाब से हास्य का मसाला डाला. एक लोकप्रिय मीम में सवाल पूछा गया—'कुत्ता संसद में क्यों गया?' जवाब था— 'क्योंकि उसे लगा कि वहां भी उसकी नस्ल के जीव मिलेंगे.' दूसरे मीम में मज़ाक था कि अगर कुत्ता अपनी पहचान ज़्यादा साफ़ करता, तो कोई दल उसे ब्रांड एंबेसडर बना देता. कुत्ता बिना बोले चला गया, और बहस पीछे छूटती चली गई. लोग आज भी तय नहीं कर पा रहे—समस्या कुत्ते से है, इंसान से, या इंसान जैसे किसी और से. जो भी हो, संसद में आया वह कुत्ता अपने व्यवहार से कम, और हमारे व्यवहार से ज़्यादा परिचित करवा गया.

संघ शताब्दी वर्ष में

आरएसएस का सतत सेवा कार्य

सुशील कुमार
(शोध छात्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला)

भारतीय समाज अपनी सहनशीलता, विविधता और समन्वय की क्षमता के लिए विश्वभर में जाना जाता है. इस विशाल और बहुरंगी समाज के बीच यदि कोई संस्था अपने ध्येय, अपने अनुशासन और अपनी मौन, सात्त्विक सेवा के कारण निरंतर जनमानस के हृदय में स्थान बनाती चली आई है, तो वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. संघ की स्थापना 1925 में डॉ. हेडगेवार द्वारा मात्र एक शाखा के रूप में हुई, किंतु लगभग एक शताब्दी के भीतर यह विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठनों में से एक बन चुका है. संघ का लक्ष्य किसी राजनीतिक लाभ, सामाजिक वर्चस्व या प्रचार-प्रसार से प्रेरित नहीं है, बल्कि उसका मूलभूत ध्येय एक संगठित, सशक्त और स्वाभिमानी राष्ट्र का निर्माण है. संघ अपने इस ध्येय को किसी वैचारिक अभियान के माध्यम से नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, संगठन तथा सतत सेवा के जरिए पूरा करने का संकल्प रखता है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा-परंपरा कोई आकस्मिक पहल नहीं है. यह संघ के मूल चिंतन—सबका हित, सबका उन्नयन का ही विस्तार है. संघ मानता है कि समाज तभी प्रगति कर सकता है जब समाज का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक परिवार तथा प्रत्येक समुदाय एक-दूसरे के लिए उत्तरदायी बने.

यही कारण है कि संघ ने प्रारंभिक वर्षों से ही शाखा-व्यवस्था में शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक संस्कारों के साथ-साथ सेवा, समरसता और सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रमुख स्थान दिया. स्वयंसेवक शाखाओं में केवल व्यायाम, बौद्धिक विचार या पठन-पाठन ही नहीं करते, बल्कि वे समाज की आवश्यकताओं को पहचानकर अपने-अपने क्षेत्रों में सेवा के छोटे-छोटे प्रकल्पों को प्रारंभ करते हैं, जो समय के साथ व्यापक और संगठित रूप लेते गए. आज स्थिति यह है कि संघ और उसके प्रेरणा से चलने वाले विविध आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से हजारों प्रकल्प पूरे देश में सक्रिय हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामविकास, आपदा प्रबंधन, सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक समरसता और स्वावलंबन जैसे अनेक क्षेत्रों में मौन तपस्या के साथ कार्य कर रहे

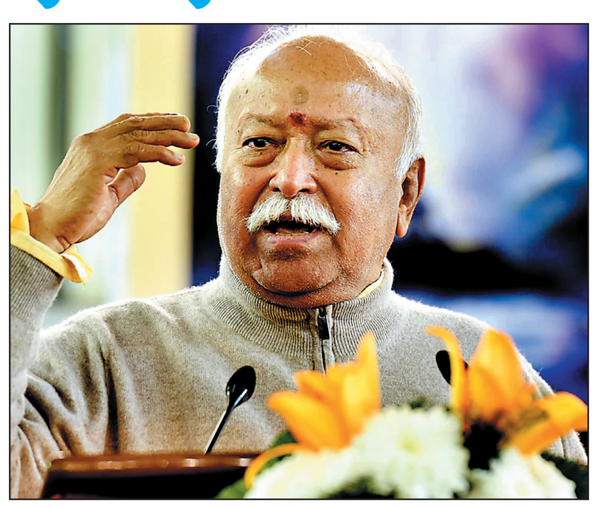

हैं. संघ के सेवा-कार्य का सबसे बड़ा आधार उसका स्वयंसेवक है. यह स्वयंसेवक किसी वेतन, पुरस्कार या पद की अपेक्षा से नहीं, बल्कि आत्मीय भाव, राष्ट्रसमर्पण और सेवा-व्रत से प्रेरित होकर कार्य करता है. संघ की शाखा में बाल स्वयंसेवक से लेकर वरिष्ठ तक, सभी में यह भाव निरंतर जागृत किया जाता है कि समाज की समस्या मेरी समस्या है, और समाज की पीड़ा मेरी पीड़ा है. यही भाव आगे चलकर संगठित सेवा-प्रकल्पों का स्वरूप लेता है. यही कारण है कि संघ का सेवा-कार्य सरकारों के बदलाव, राजनीतिक परिस्थितियों या बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से नहीं बदलता; वह निरंतर, अविराम और आत्मनिष्ठा पर आधारित होता है.

आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके प्रेरित संगठनों द्वारा देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों, आदिवासी क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों तथा शहरी मलिन बस्तियों तक में सेवा के हजारों प्रकल्प संचालित हो रहे हैं. इन प्रकल्पों में सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती, भारत विकास परिषद, दीनदयाल शोध संस्थान, अरुणा सामाजिक सेवा संस्थान, राष्ट्रीय सेवा भारती, जनकार्य सेवा संघ तथा अन्य अनेक संगठन अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं. ये सभी संगठन एक ही ध्येय से प्रेरित हैं—सेवा ही संगठन, सेवा ही राष्ट्र-निर्माण. इन संगठनों की गतिविधियाँ प्रचार-प्रसार के माध्यम से कभी सामने नहीं आतीं, फिर भी इनके प्रयासों का विस्तार इतना विशाल है कि यह देश में सबसे बड़े सामाजिक सेवा-नेटवर्क के रूप में माना जाता है. शिक्षा क्षेत्र में, संघ प्रेरित संगठनों द्वारा सैकड़ों विद्यालय, आवासीय छात्रावास, संस्कार केंद्र और बाल-संस्कार वर्ग चलाए जा रहे हैं. विद्या भारती के अंतर्गत चलने वाले विद्यालय न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, बल्कि शिक्षा को भारतीय दृष्टि, भारतीय मूल्य और सामाजिक समरसता के साथ जोड़ते हैं. इन विद्यालयों में लाखों विद्यार्थी बिना किसी भेदभाव के पढ़ाई करते हैं. इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्रों में चलने वाले एकल विद्यालय, जनजाती छात्रावास तथा सेवा भारती के संस्कार केंद्र उन बच्चों तक शिक्षा पहुँचा रहे हैं जिनके लिए शिक्षा कभी दूर की चीज थी. स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी संघ प्रेरित संगठनों ने एक व्यापक तंत्र विकसित किया है.

सेवा भारती द्वारा संचालित चल चिकित्सा केंद्र, निःशुल्क या न्यून शुल्क पर चलने वाले अस्पताल, चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्रदान अभियान, कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास केंद्र और पोषण योजनाएँ समाज के कमजोर वर्गों तक स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. कोरोना वैश्विक महामारी ने यह साबित कर दिया कि संघ का यह सेवा-तंत्र कितना सक्षम, समर्पित और संकट-स्थितियों में निर्णायक भूमिका निभाने वाला है. महामारी के दौरान लाखों स्वयंसेवकों ने भोजन-सामग्री वितरण, दवाइयाँ पहुँचाने, प्लाज़्मा दान, अस्पतालों की सहायता, प्रवासी मजदूरों की मदद और अंतिम संस्कार तक के कार्यों को बिना किसी प्रचार के पूरी निष्ठा से संपन्न किया. ग्राम-विकास और स्वावलंबन संघ की विचारधारा के प्राणतत्व हैं. दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांतों को आधार बनाकर ईश्वरीय मार्गदर्शन की तरह समाज-सेवा को व्यवहारिक रूप देने का कार्य दीनदयाल शोध संस्थान (चिनहट, चित्रकूट) ने किया है. इसके माध्यम से 'समग्र ग्राम विकास' मॉडल विकसित हुआ, जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल-संरक्षण, कौशल-विकास, महिला सशक्तिकरण और पशुपालन जैसी अनेक इकाइयों को एकीकृत करके आत्मनिर्भर ग्रामों का निर्माण किया गया.

मध्य प्रदेश में 80% युवा महिलाएं श्रम शक्ति से अनुपस्थित

मोहनसुंदरी थंगावेल
प्रोपेसर आईआईटी इंदौर

15-59 वर्ष की आयु की महिलाएं श्रम बल में हैं, और युवा महिलाओं (15-29) के लिए यह आंकड़ा 17.9 प्रतिशत तक गिर जाता है, जिससे 80 प्रतिशत से अधिक पूरी तरह से काम से विमुख हो जाती हैं (सीईडीए, 2024). सुरक्षित, सामाजिक रूप से स्वीकार्य सार्वजनिक परिवहन के बिना, इस बहिष्कार में बदलाव की संभावना नहीं है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों (एसआरटीयू) की समीक्षा से पता चलता है कि यह अंतर कितना गहरा है. तमिलनाडु 22,000 से अधिक राज्य बसें (प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 305) संचालित करता है, दिल्ली 5,573 (प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 332) चलाती है, लेकिन मध्य प्रदेश ने 2018-19 के आंकड़ों (एमओआरटीएच, 2019) में किसी भी राज्य बस बेड़े की सूचना नहीं दी. यह गतिशीलता की कमी सीधे रोजगार की कमी को दर्शाती है.

भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार, प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 236 व्यक्ति के जनसंख्या घनत्व के साथ, गाँव दूर-दूर तक फैले हुए हैं. यात्रियों का घनत्व कम है, जिससे कई ग्रामीण मार्ग निजी बस संचालकों के लिए लाभहीन हो जाते हैं. यही कारण है कि कनेक्टिविटी अनियमित बनी हुई है और विशुद्ध रूप से व्यावसायिक परिवहन मॉडल सफल नहीं हो पा रहे हैं.लेकिन ग्रामीण विकास की बात करें तो मुनाफ़ा ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए. जिस तरह सरकारें स्कूलों, क्लीनिकों या पेयजल में निवेश करती हैं, उसी तरह सार्वजनिक परिवहन भी मानव-पूंजी आधारित बुनियादी ढाँचे का एक रूप है. यह तत्काल किराया-बक्से राजस्व के बजाय दीर्घकालिक और सामाजिक लाभ प्रदान करता है. जिन राज्यों ने सार्वजनिक बस सेवाओं को सब्सिडी दी है, उन्होंने साक्षरता, महिला कार्यबल भागीदारी और औद्योगिक विकास के रूप में इसका लाभ उठाया है.

ज़मीनी स्तर की एक कहानी: महिलाएँ साइकिल या साइकिल क्यों नहीं चलातीं- एक सुबह, मेरी घरेलू सहायिका ने बताया कि वह काम पर पहुँचने के लिए रोज़ाना 4 से 5 किलोमीटर पैदल क्यों जाती है. मैंने पूछा कि वह साइकिल या स्कूटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करती, जिससे उसका समय और ऊर्जा बच

सकती है. मुझे लगा कि वहनीयता ही समस्या है. लेकिन उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया-मैं एक घर की बहू हूँ, लड़की नहीं. मैं बहू हूँ, लड़की नहीं. हालाँकि मुझे साइकिल चलाना आता है, मैं चला नहीं सकती. हमारे गाँव में 90% महिलाएँ स्कूटर चलाना नहीं जानतीं. उनके शब्द मध्य प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण इलाकों की सामाजिक सच्चाई को दर्शाते हैं- महिलाओं के पास साधन होने पर भी, सामाजिक मानदंड उनकी गतिशीलता को सीमित करते हैं. निजी वाहन मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वे महिलाओं के लिए हमेशा उपलब्ध या स्वीकार्य नहीं होते. उनके लिए, बसें ही परिवहन का एकमात्र सुरक्षित, वैध और किफ़ायती साधन हैं.

बसें महिलाओं के लिए बुनियादी ढाँचा क्यों हैं- बसें गाँवों को शहरों से जोड़ने से कहीं ज़्यादा काम करती हैं; ये सम्मान और सुरक्षा भी प्रदान करती हैं. स्कूटर या साइकिल के विपरीत, बसों को सामाजिक मान्यता प्राप्त है क्योंकि बस में सवार होने वाली महिला को उसी तरह के अपमान या प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ता. बसें संख्या, व्यवस्थित समय-सारिणी और पूर्वानुमेय मार्गों के मामले में भी मज़बूती प्रदान करती हैं, जिससे उत्पीड़न या अलगाव का जोखिम कम होता है जो ग्रामीण महिलाओं को यात्रा करने से हतोत्साहित करता है. साक्ष्य बताते हैं कि जहाँ बसों का विस्तार होता है, वहाँ महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ती है. उद्योगों को विश्वसनीय महिला श्रम से लाभ होता है, स्कूलों में लड़कियों का नामांकन और ठहराव बढ़ता है, और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होता है क्योंकि महिलाओं की क्लीनिकों तक पहुँच आसान हो जाती है. मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ 80 प्रतिशत से ज़्यादा युवा महिलाएँ श्रम शक्ति से अनुपस्थित हैं, बसें सिर्फ वाहन नहीं, बल्कि समानता लाने वाली हैं.

मध्य प्रदेश के लिए आगे का रास्ता - मध्य प्रदेश के लिए आगे का रास्ता स्पष्ट है:सामाजिक रूप से आवश्यक लेकिन व्यावसायिक रूप से अव्यवहारिक मार्गों के लिए वित्तीय सहायता के साथ एक राज्य-संचालित ग्रामीण बस निगम बनाएँ.ज़ महिलाओं की ज़रूरतों के अनुसार बस सेवाओं का डिज़ाइन तैयार करें, जिनके रूट और समय स्कूलों, कॉलेजों और फ़ैक्टरी शिफ्टों के साथ-साथ सुरक्षा सुविधाओं के अनुसार हों.

- बसों को औद्योगिक बुनियादी ढाँचे के रूप में देखें, गाँवों को औद्योगिक गलियारों से जोड़ें ताकि फ़ैक्टरियाँ ग्रामीण श्रम का उपयोग कर सकें.
- बिखरे हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त छोटी, ईंधन-कुशल बसों में निवेश करें.

ऐसी प्रणाली की लागत दीर्घकालिक लाभों की तुलना में मामूली होगी- बेहतर शिक्षा, महिला कार्यबल में अधिक भागीदारी, और एक औद्योगिक कार्यबल जो मध्य प्रदेश के विकास को गति दे सकता है.

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश में सड़कें पहले ही बन चुकी हैं; अब विकास को गति देने के लिए उन पर बसें चलानी होंगी. सड़कों के अस्तित्व के बावजूद, परिवहन साधनों की अनुपस्थिति अधिकांश महिलाओं और युवाओं के लिए अवसरों को पहुँच से बाहर कर देगी. हालाँकि, बसों के माध्यम से, राज्य परिवहन को विकास के इंजन में बदल सकता है- छात्रों को स्कूल, महिलाओं को कार्यस्थल और श्रमिकों को कारखानों तक पहुँचाना. बसें केवल आवागमन के लिए नहीं हैं. वे समावेशिता, समानता और अवसर के लिए हैं. मध्य प्रदेश के लिए, उनमें निवेश करने का समय अभी है.

संदर्भ आर्थिक आँकड़ा एवं विश्लेषण केंद्र (सीईडीए). (2024). पाँच राज्यों में श्रम बल भागीदारी के पैटर्न का खुलासा.
अशोक विश्वविद्यालय.